राष्ट्रीय संस्करण

वर्ष 3 अंक 235

दैनिक जागरण

मूल्य ₹6.00, नई दिल्ली, शनिवार, 1 फरवरी 2020

www.jagran.com

पृष्ठ 16

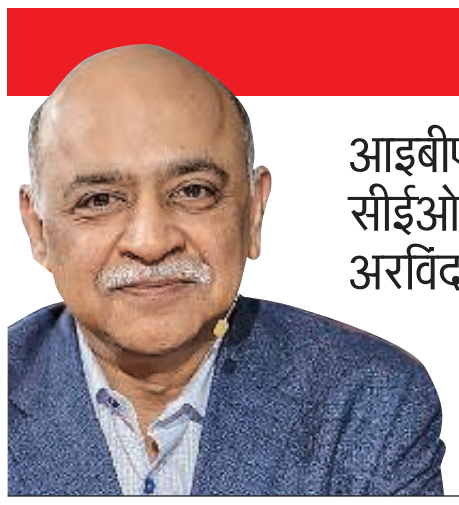

आइबीएम के सीईओ चुने गए अरविंद कृष्णा

>> 7

अगले दशक में देश की विकास गाथा का एजेंडा तय करेगा बजट

जयप्रकाश रंजन ● नई दिल्ली

मोदी सरकार के मौजूदा कार्यकाल का दूसरा बजट कुछ वैसा ही होगा, जिसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी टीम को जाना जाता है। यानी चुनौतियों को दरकिनार करते हुए पहले बड़ा लक्ष्य तय करना और फिर उसे हासिल करने के लिए पूरी ताकत लगा देना। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा शनिवार को पेश किया जाने वाला आम बजट 2020-21 अगले दशक में देश की विकास गाथा का पूरा रोडमैप पेश करने वाला होगा।

वित्त मंत्रालय की तरफ से तैयार आर्थिक सर्वेक्षण 2019-20 का संकेत है कि वित्तीय सुधारों को लेकर निर्भीक फैसला भी लिया जाएगा और एक दशक में हर हाथ को काम देने की दिशा में भी आगे बढ़ा जाएगा। यह भी तय है कि वित्त मंत्री राजकोषीय प्रबंधन को लेकर फिलहाल बहुत फिक्रमंद नहीं होंगी। वह निवेश, बचत और निर्यात को बढ़ाने वाला बजट पेश करेंगी, ताकि लंबे समय तक तेज आर्थिक विकास दर हासिल की जा सके।

शुक्रवार को पेश आर्थिक सर्वेक्षण के मुताबिक चालू वित्त वर्ष में विकास दर पांच फीसद पर सिमटने के बाद 2020-21 में छह से साढ़े छह फीसद रहेगी।

यह निश्चित तौर पर देश की आर्थिक सेहत के लिए थोड़ी बेहतर स्थिति होगी, लेकिन वित्त वर्ष 2024-25 तक देश की अर्थव्यवस्था को पांच लाख करोड़ डॉलर (फाइव ट्रिलियन डॉलर) तक पहुंचाने के लक्ष्य के लिए नाकाफी होगी। आर्थिक सर्वेक्षण में स्पष्ट रूप से यह कहा गया है कि अगले पांच साल तक आठ फीसद की सालाना वृद्धि दर से ही सरकार यह लक्ष्य हासिल कर सकती है। हालांकि, आर्थिक मामलों के विशेषज्ञों का मानना है कि यह दर कम से कम 10 फीसद होनी चाहिए।

विशेष पेज >> 10-11

6-6.5%
अगले वित्त वर्ष में सुधार के साथ रह सकती है विकास दर

8%
की विकास दर चाहिए अगले पांच साल तक पांच लाख करोड़ डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने के लिए

3.3%
से बढ़कर राजकोषीय घाटा 3.8 फीसद पर पहुंचने का अनुमान

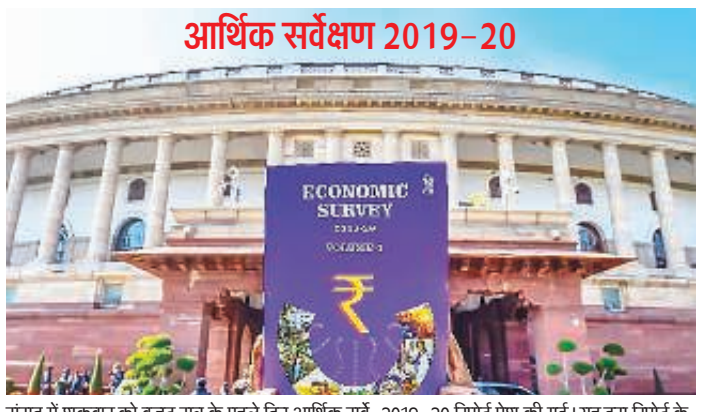

संसद में शुक्रवार को बजट सत्र के पहले दिन आर्थिक सर्वे-2019-20 रिपोर्ट पेश की गई। यह इस रिपोर्ट के पहले खंड का कवर है ● प्रेट्र

क्या मिल रहे हैं संकेत?

- सुधारों को लेकर उठाए जा सकते हैं अप्रत्याशित कदम
- आजमाए जा सकते हैं बचत बढ़ाने के नए उपाय
- ग्रामीण विकास के लिए आवंटन में होगी भारी वृद्धि
- वानिकी, डेयरी व मछली पालन को मिलेगा बढ़ावा
- निर्यात से रोजगार बढ़ाने को नई रणनीति का एलान संभव
- देश में कारोबार की राह सुगम बनाने की पहल होगी तेज
- एसएमई के लिए फंड का होगा इंतजाम
- मौजूदा जरूरत को देखते हुए खर्च बढ़ाने पर रहेगा जोर
- खाद्य सब्सिडी पर जारी बहस के बीच चल सकती है कैंची
- आवश्यक वस्तु अधिनियम में बदलाव भी संभव
- राजकोषीय प्रबंधन पर ज्यादा फिक्र नहीं करेगी सरकार

हर मोर्चे पर चुनौती

लंबे समय तक तेज विकास दर के लिए निवेश, बचत व निर्यात में लगातार वृद्धि बेहद जरूरी है। भारतीय अर्थव्यवस्था उक्त तीनों मामलों में पिछड़ रही है। तीनों सेक्टरों में जान फूंकने के लिए सुधारों का नया डोज देना होगा। वित्त मंत्रालय के आर्थिक सलाहकार कृष्णमूर्ति सुब्रमणियन ने कहा, निवेश व बचत को बढ़ाने की कोशिश सतत प्रक्रिया है। विकास दर में गिरावट निचले स्तर पर है और अब आगे इसमें सुधार ही होना है।

विनिवेश पर बढ़ेंगे आगे

इस वर्ष भले ही 1.05 लाख करोड़ का विनिवेश लक्ष्य हासिल होता नहीं दिख रहा हो, लेकिन अगले वित्त वर्ष में भी लक्ष्य बड़ा रखा जाएगा। सरकार मान रही है कि आर्थिक हालात सुधरने के साथ ही विनिवेश प्रक्रिया भी तेज होगी। आर्थिक सर्वेक्षण ने निर्यात के जरिये बेरोजगारी खत्म करने का नुस्खा बताया है। सरकारी बैंकों की स्थिति पर निराशा को देखते हुए बजट में इस दिशा में भी बड़े एलान की उम्मीद है।

2018-19 की विकास दर घटकर 6.1 फीसद हुई

राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनएसओ) के संशोधित आंकड़ों में वित्त वर्ष 2018-19 की विकास दर को 6.8 फीसद से घटाकर 6.1 कर दिया गया है। यह संशोधन खनन, मैन्यूफैक्चरिंग व खेती के प्रदर्शन में कमी की वजह से किया गया है। एनएसओ ने बताया कि 2011-12 की कीमतों के आधार पर 2018-19 व 2017-18 में रीयल जीडीपी 139.81 लाख करोड़ और 131.75 लाख करोड़ रुपये रहा है। 2017-18 की विकास दर भी पुनः संशोधित करते हुए 7.2 से घटाकर सात परसेंट कर दी गई है।

सरोकार

गंगासागर पहुंच 'पुण्य' कमाते हैं डॉक्टर भाई-बहन

कोलकाता : सारे तीरथ बार-बार, गंगासागर एक बार! लोग आस्था के

महापर्व मकर संक्रांति पर एक बार भी गंगासागर पहुंच जाने को सौभाग्य मानते हैं, वहीं यह डॉक्टर भाई-बहन 40 साल से हर बार यहां पहुंच सेवा कर पुण्य कमाते आ रहे हैं। (पेज-7)

जागरण विशेष

तकनीकी क्रांति ला सकता है एटोसेकंड स्ट्रीक कैमरा

भोपाल : एटोसेकंड स्ट्रीक कैमरा नामक 4डी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से

इलेक्ट्रॉन की गति को लाइव देखा जा सकता है। जर्मनी में कार्यरत वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉ. मनीष गर्ग का आविष्कार इलेक्ट्रॉनिक्स, मेडिकल, कंप्यूटिंग क्षेत्र में क्रांति ला सकता है। (पेज-6)

न्यूज गैलरी

राज-नीति ▶ पृष्ठ 4

घपले के आरोपित आइएएस अफसरों को राहत नहीं

रायपुर : छत्तीसगढ़ में भाजपा शासनकाल में हुए करीब एक हजार करोड़ रुपये के घोटाले में आरोपित सात आइएएस समेत 12 अधिकारियों को हाई कोर्ट से राहत नहीं मिली है। उनके खिलाफ सीबीआइ को मुकदमा दर्ज करने का हाई कोर्ट ने निर्देश दिया है, जिससे टॉप ब्यूरोक्रेसी में खलबली मची है।

अंतरराष्ट्रीय ▶ पृष्ठ 13

ब्रिटेन ने आधी रात यूरोपीय यूनियन को कहा बाय

लंदन : ब्रिटेन आधी रात को यूरोपीय यूनियन (ईयू) से अलग हो गया। इसके साथ ही ईयू सदस्य देशों के साथ उसकी 47 साल पुरानी आर्थिक, राजनीतिक और कानूनी एकजुटता खत्म हो गई। ईयू से अलग होने यानी ब्रेक्जिट पर शुक्रवार को ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने कहा, 'यह नए युग की शुरुआत है।'

सीएए पर मोदी सरकार के तेवर सख्त

रक्षात्मक होने की जरूरत नहीं : प्रधानमंत्री

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

- कहा, आक्रामक तरीके से अपना पक्ष रखें सदस्य
- कानून मुस्लिम विरोधी नहीं, दुष्प्रचार कर रहा विपक्ष

यह तय है कि बजट सत्र में सत्तापक्ष और विपक्ष के बीच बयानों में घमासान देखने को मिलेगा। एक तरफ जहां विपक्ष नागरिकता संशोधन कानून (सीएए), राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (एनपीआर) को एकजुटता का सबसे बड़ा शस्त्र मानकर विरोध को और धारदार बनाने की कोशिश में जुटा है। वहीं, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के अभिभाषण के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) के अपने साथियों से स्पष्ट कहा है कि इस मुद्दे पर रक्षात्मक होने की जरूरत नहीं है। बल्कि आक्रामक तरीके से अपना पक्ष रखना है।

बजट सत्र के लिए रणनीति तैयार करने के लिए आयोजित राजग की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, 'विपक्ष सीएए को मुस्लिम विरोधी होने का दुष्प्रचार कर रहा है, जबकि सच्चाई यह है कि हमारे लिए अल्पसंख्यक भी उतने ही अपने हैं, जितने अन्य दूसरे नागरिक।'

बैठक के बाद राजग की सहयोगी लोक जनशक्ति पार्टी के नेता और केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान ने कहा कि नागरिकता संशोधन कानून के मुद्दे पर राजग पूरी तरह एकजुट है और चट्टान की तरह प्रधानमंत्री मोदी के साथ खड़ा है। उल्लेखनीय है कि इस मामले में पहले थोड़ा अलग रुख दिखा रहा शिरोमणि अकाली दल (बादल) अब पूरी तरह साथ आ गया है। वहीं जनता दल यूनाइटेड (जदयू) ने अलग राग अलाप रहे नेताओं को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बजट सत्र के मौके पर राजग के वरिष्ठ नेताओं के साथ बैठक करते हुए। एएनआइ

प्रधानमंत्री के अलावा केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह पहले भी बार-बार कह चुके हैं कि नागरिकता संशोधन कानून से पीछे हटने का कोई सवाल ही नहीं है। दरअसल सर्वोच्च न्यायालय ने भी पिछले निर्णय में इस पर रोक लगाने से साफ इन्कार कर दिया था। नैतिक आधार पर सरकार के साथ महात्मा गांधी से लेकर पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी और पूर्व प्रधानमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मनमोहन सिंह तक के बयान हैं। ऐसे में वर्तमान सत्र में घमासान होना लाजिमी है।

नागरिकता कानून ऐतिहासिक : राष्ट्रपति

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

- कहा, विरोध के नाम पर हिंसा की जगह नहीं
- कानून को गांधी जी की इच्छाओं के अनुरूप बताया

नागरिकता संशोधन कानून को ऐतिहासिक फैसला बताते हुए राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भी साफ संदेश दे दिया कि विरोध प्रदर्शनों के दबाव में सरकार इस पर झुकने वाली नहीं है। साथ ही विरोध प्रदर्शन के नाम पर हिंसा को खारिज करते हुए राष्ट्रपति ने दो टूक कहा कि बहस-चर्चा ही विवाद समाधान का रास्ता है। बजट सत्र की शुरुआत से पहले राष्ट्रपति संसद के संयुक्त सत्र को संबोधित कर रहे थे।

सीएए पर विपक्षी सांसदों की नारेबाजी और विरोध के बीच अपने अभिभाषण में राष्ट्रपति ने नागरिकता संशोधन कानून को महात्मा गांधी की इच्छा के अनुरूप बताते साफ कहा कि पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों पर होने वाले अत्याचार के मद्देनजर इस कानून का लाया जाना अपरिहार्य था। उन्होंने कहा कि विभाजन के बाद बने माहौल में गांधीजी ने साफ कहा था कि 'पाकिस्तान के हिंदू और सिख, जो वहां नहीं रहना चाहते, वे भारत आ सकते हैं, उन्हें सामान्य जीवन मुहैया कराना भारत सरकार का कर्तव्य है।' उन्होंने सीएए पारित करने के लिए संसद के दोनों सदनों के सदस्यों का अभिनंदन करते हैं।

राष्ट्रपति ने कहा कि पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों पर अत्याचार और बढ़ा है और ननकाना साहिब की घटना इसका ताजा प्रमाण है। पाकिस्तान में अल्पसंख्यक समुदाय पर हो रहे अत्याचार की निंदा करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि यह हम सभी का दायित्व है कि विश्व के

नई दिल्ली में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद बजट सत्र से पहले दोनों सदनों के संयुक्त सत्र को संसद के केंद्रीय कक्ष में संबोधित करने के दौरान। प्रेट्र

सामने पाक के ऐसे कृत्यों को बेनकाब किया जाए। सीएए के खिलाफ चल रहे विरोध प्रदर्शनों का जिक्र किए बिना राष्ट्रपति ने कहा कि विरोध के नाम पर किसी तरह की हिंसा समाज और देश को कमजोर करती है। सरकार का मानना है कि चर्चा-बहस और वाद-विवाद ही लोकतंत्र को मजबूत करते हैं और समाधान का रास्ता निकालते हैं। सीएए पर राष्ट्रपति के इस नजरिए पर सत्तापक्ष के सदस्यों ने जहां मेजें थपथपाईं वहीं, उत्तेजित विपक्षी सदस्यों ने भी जमकर नारेबाजी और शोर शराबा किया। (संबंधित खबरें पेज-3 पर)

निर्भया के दोषियों की फिर टली फांसी

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली : निर्भया सामूहिक दुष्कर्म व हत्या मामले में चारों दोषियों की फांसी पर पटियाला हाउस कोर्ट ने अगले आदेश तक रोक लगा दी है। दोषी पवन गुप्ता, विनय कुमार शर्मा और अक्षय कुमार सिंह के अधिवक्ता एपी सिंह ने कानूनी विकल्प शेष होने का हवाला देते हुए डेथ वारंट पर रोक की अर्जी दायर की थी। चौथे दोषी मुकेश ने सभी उपाय इस्तेमाल कर लिए हैं। 17 जनवरी को एक फरवरी के लिए डेथ वारंट जारी हुआ था। शुक्रवार को इस अर्जी पर लंबी बहस के बाद फैसला सुरक्षित रखा गया। करीब चार घंटे के इंतजार के बाद अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश धर्मेंद्र राणा ने अगले आदेश तक फांसी पर रोक लगाने का आदेश दिया। तिहाड़ जेल प्रशासन को आदेश दिया कि शनिवार को प्रगति रिपोर्ट दाखिल करे।

दोषियों की याचिका में कहा गया था कि फांसी पर अनिश्चित काल तक रोक लगा देनी चाहिए। सुनवाई के दौरान तिहाड़ जेल के अधिवक्ता ने कोर्ट को बताया कि दोषी विनय को छोड़कर किसी की भी दया या अन्य कोई याचिका विचाराधीन नहीं है। लिहाजा तीन लोगों को शनिवार सुबह फांसी दी जा सकती है। मुकेश की अधिवक्ता वृंदा ग्रोवर ने कहा, जब एक साथ डेथ वारंट जारी हुआ है तो अलग-अलग फांसी नहीं दी जा सकती।

वकीलों की भूमिका पर उठाए सवाल पेज>>6

ड्रोन से रखी निगाह, फिर ढेर किए तीन आतंकी

राज्य ब्यूरो, जम्मू

- मुठभेड़ में एक पुलिसकर्मी व सीआरपीएफ के दो जवान घायल
- प्लास्टिक के पाउडर की बोरियों से लदे ट्रक में छिपे थे जैश आतंकी

बड़ी वारदात की मंशा से ट्रक में छिपकर कश्मीर जा रहे जैश-ए-मुहम्मद के तीन आतंकियों को सुरक्षाबलों ने जम्मू-श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग में नगरोटा के बन इलाके में मार गिराया। इनसे स्नाइपर राइफल सहित भारी मात्रा में हथियार व अन्य सामान बरामद हुआ है। मुठभेड़ में एक पुलिसकर्मी और सीआरपीएफ के दो जवान घायल हो गए। ट्रक के चालक, सहचालक और एक सवार से पूछताछ की जा रही है।

पुलिस महानिदेशक दिलबाग सिंह के मुताबिक मारे गए आतंकी पाकिस्तानी हैं, जो कठुआ के हीरानगर सीमा से घुसे थे। ट्रक चालक उनका ओवर ग्राउंड वर्कर था। आतंकियों ने गुरुवार शाम इसी ट्रक में छिप कर रात गुजारी थी। सूत्रों के अनुसार आतंकी जम्मू-श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर सुरक्षा संस्थानों को भी निशाना बनाने की ताक में थे।

जम्मू शहर से 28 किमी दूर बन टोल प्लाजा पर शुक्रवार सुबह पांच बजे पालीविनाइल क्लोराइड की बोरियों से लदा ट्रक (जेके03एफ-1478) रुका। चालक समीर और सह चालक आसिफ मलिक तलाशी से आनाकानी करने लगे तो शक हुआ। पुलिस और केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआइएसएफ) जवान सामान की तलाशी लेने लगे।

ट्रक के बाईं तरफ छोटे दरवाजे को खुलवाया तो अंदर छिपे आतंकियों ने गोलीबारी शुरू कर दी, पुलिसकर्मी भूमराज सिंह के हाथ में गोली लगी। तब तक एक आतंकी ने बोरियां हटाकर बाहर निकलने की कोशिश की। वह कुछ कर पाता कि टोल प्लाजा कार्यालय की छत पर तैनात सीआरपीएफ जवान ने उसे मार गिराया। फायरिंग के बीच दो आतंकियों ने ग्रेनेड फेंका। इसके बाद स्मोक बम फेंका और धुएं की आड़ में साथ की खाई में कूद जंगल में भाग निकले। ग्रेनेड फटने से सीआरपीएफ जवान संजीव कुमार व पासवान घायल हो गए। करीब पौने छह बजे सेना, पुलिस, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल व सीआइएसएफ ने जंगल को घेर लिया। सेना ने हेलीकॉप्टरों व ड्रोन से आतंकियों की निगरानी शुरू की। करीब एक किलोमीटर जंगल में चले गए आतंकियों की सटीक लोकेशन उस समय पता चली जब उन्होंने एक ड्रोन को निशाना बनाया। मॉनिटर पर आतंकियों को देख सुरक्षाबलों ने उन्हें मार गिराया। अफसरों, के अनुसार, ट्रक चालक समीर डार, सह चालक आसिफ मलिक व एक अन्य सवार आसिफ अहमद को नगरोटा थाने ले जाया गया। आसिफ गाइड बताया जा रहा है।

आतंकियों के पास से ये हुई बरामदगी पेज>>6

भारत की लगातार दूसरी 'सुपर जीत'

वेलिंगटन, प्रेट्र : भारतीय टीम ने शुक्रवार को वेलिंगटन में चौथे टी-20 में न्यूजीलैंड को लगातार दूसरी बार सुपर ओवर में हराकर पांच मैचों की सीरीज में 4-0 की बढ़त लेने के साथ ही क्लीन स्वीप की तरफ कदम बढ़ा दिए। इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ जब दो टीमों के बीच लगातार दो मैचों का निर्णय सुपर ओवर से हुआ।

वेस्ट पैक स्टेडियम में भारत ने 20 ओवर में आठ विकेट पर 165 रन बनाए। न्यूजीलैंड की टीम एक समय जीत की ओर बढ़ रही थी लेकिन मैन ऑफ द मैच शार्दुल ठाकुर के आखिरी ओवर की बदौलत मेजबान 20 ओवर में सात विकेट पर 165 रन ही बना सके। मैच टाई हुआ जिसके बाद सुपर ओवर का सहारा लिया गया। न्यूजीलैंड ने सुपर ओवर में 13 रन बनाए और टीम इंडिया को जीत के लिए 14 रन का लक्ष्य मिला। भारत ने पांच गेंदों पर एक विकेट खोकर लक्ष्य हासिल कर लिया।

भारत ने सुपर ओवर में लगातार दूसरा मैच जीतकर सीरीज में 4-0 की बढ़त ली

वेलिंगटन में जीत के बाद खुशी जाहिर करते विराट कोहली। प्रेट्र (पेज-14 भी देखें)

04 बार जसप्रीत बुमराह ने टी-20 क्रिकेट (आइपीएल भी शामिल) में सुपर ओवर फेंका और हर बार टीम जीती है। अंतरराष्ट्रीय टी-20 में बुमराह ने दोनों ही बार सुपर ओवर फेंका और टीम इंडिया जीती

06 बार साउथी ने सुपर ओवर में गेंदबाजी की जिसमें पांच बार न्यूजीलैंड की टीम को हार का सामना करना पड़ा। न्यूजीलैंड ने टी-20 में सात और वनडे में एक बार सुपर ओवर खेला है जिसमें उसे सिर्फ एक बार जीत मिली है

2006 में न्यूजीलैंड व वेस्टइंडीज के बीच खेला गया मैच टाई हुआ। यह अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में पहला टाई टी-20 मुकाबला था। वेस्टइंडीज और न्यूजीलैंड का मैच 126 के स्कोर पर टाई रहा। ऑकलैंड में हुए इस मैच को कीवी टीम ने बॉल आउट में 3-0 से जीता था।

थालीनॉमिक्स

जनता को बजटीय गणित समझाने के लिए सरकार ने नया तरीका खोजा है, सरकार ने सरल शब्दों में लोगों को बताया कि गत छह वर्षों में उसके खाने की थाली कितनी सस्ती हुई है

थाली का बजट सुधरा, शाकाहारी रहना हुआ ज्यादा सस्ता

नई दिल्ली, प्रेट्र : अर्थशास्त्र का लोगों के जीवन पर बहुत असर पड़ता है। बावजूद इसके कुछ सीधी-सपाट बातों के अलावा लोग इसमें ज्यादा रुचि नहीं दिखाते हैं। कई बार सरकार का लाखों-करोड़ों का बजट लोगों को समझ से बाहर लगने लगता है। इस बार सरकार ने लोगों की इस परेशानी को दूर करने की दिशा में पहल की है। आर्थिक सर्वेक्षण में बाकायदा थालीनॉमिक्स का एक अध्याय जोड़ा गया है। इसमें सरकार ने यह समझाने की कोशिश की है कि पिछले पांच साल में उठाए गए कदमों से लोगों का खाना कितना सस्ता हुआ है।

थालीनॉमिक्स में यह समझाया गया है कि सरकार के कदमों ने पांच सदस्यों वाले परिवार की जेब में सालाना कितने रुपये बचाए हैं। इसके लिए 25 राज्यों व केंद्रशासित प्रदेशों के औद्योगिक कर्मियों के लिए महंगाई की दर का आकलन किया गया। थाली की कीमत जानने के लिए अप्रैल, 2006 से अक्टूबर, 2019 तक की कीमतों को समाहित किया गया। थाली पर होने वाले खर्च की गणना करने के लिए आय में वृद्धि से लेकर अन्य सभी पैमानों का ध्यान रखा गया। इसमें देश के चारों हिस्सों उत्तर, दक्षिण, पूर्व एवं पश्चिम में एक थाली की एब्सोल्यूट कीमत का आकलन किया गया। चारों ही क्षेत्रों में 2015-16 से थाली की कीमतें कम हुई हैं। एक औसत औद्योगिक कर्मचारी की सालाना आय के हिसाब से गणना करें तो 2006-07 की तुलना में 2019-20 में शाकाहारी थाली की कीमत 29 फीसद कम हो गई है। वहीं इसी अवधि में मांसाहारी थाली की कीमत में 18 फीसद की कमी आई है।

- सरकार ने आर्थिक सर्वेक्षण में जोड़ा थालीनॉमिक्स का अध्याय
- सरकार के कदमों से 29 फीसद सस्ती हुई शाकाहारी थाली
- मांसाहारी थाली भी 18 फीसद सस्ती, जेब में बच रहे सालाना 11787 रुपये

प्रतीकात्मक

2015-16 से शुरू हुई गिरावट

थाली की कीमत में गिरावट का सिलसिला 2015-16 से शुरू हुआ। इससे पहले कीमतें लगातार बढ़ रही थीं। कृषि क्षेत्र में उत्पादकता बढ़ाने की दिशा में 2014-15 में सरकार ने कई सुधारवादी कदम उठाए थे। साथ ही कीमतों में पारदर्शिता लाने के लिए कृषि बाजारों में भी प्रक्रियात्मक सुधार किए गए थे। इनका नतीजा भी सालभर बाद ही दिखने लगा और 2015-16 में कीमतों में गिरावट शुरू हो गई। 2019 में कीमतों में कुछ बढ़ोतरी के बाद भी प्रभावी तौर पर एक थाली की कीमत कम हुई है।

जेब में कितना बचा?

आर्थिक सर्वेक्षण में बताया गया है कि यदि 2015-16 से पहले वाली तेजी बनी रहती हो आज की तारीख में शाकाहारी थाली पर पांच सदस्यों वाले एक परिवार को सालाना 10,887 रुपये ज्यादा खर्च करने पड़ते। यानी कीमतें कम होने से एक परिवार ने सालाना 10,887 रुपये बचाए हैं। इसी तरह मांसाहारी थाली पर सालाना 11,787 रुपये की बचत हुई है।

थाली मतलब क्या?

शाकाहारी थाली में सरकार ने अनाज, सब्जी और दाल को शामिल मानते हुए आकलन किया है। इसी तरह मांसाहारी थाली में अनाज, सब्जी और एक मांसाहारी भोजन शामिल है। इस प्रक्रिया में सरकार ने भोजन पकाने में इस्तेमाल होने वाले नमक, मसाले व अन्य सभी घटकों को भी ध्यान में रखते हुए कीमत का आकलन किया है।

दिल्ली में दो रुपये किलो आटा व छात्राओं को स्कूटी देगी भाजपा

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली

- भाजपा ने पेश किया दिल्ली के विकास का संकल्प पत्र

दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा द्वारा शुक्रवार को जारी संकल्प पत्र में विश्वस्तरीय बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने, प्रदूषण, सार्वजनिक परिवहन और दूषित पानी की समस्या से निजात दिलाने का वादा किया गया है। साथ ही गरीबों को दो रुपये किलो आटा और कॉलेज में जाने वाली गरीब बेटियों को इलेक्ट्रिक स्कूटी और नौवीं की छात्रा को साइकिल देने का एलान किया है। गरीबों को पांच लाख तक की मुफ्त इलाज की सुविधा देने वाली प्रधानमंत्री आयुष्मान योजना व प्रधानमंत्री आवास योजना भी लागू करने की बात है।

भाजपा ने कहा है कि मेरी दिल्ली, मेरा सुझाव अभियान के तहत 11.65 लाख लोगों से मिले सुझाव के आधार पर संकल्प पत्र तैयार किया गया है। प्रदेश भाजपा कार्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा, दिल्ली को सर्वश्रेष्ठ शहर बनाने की ताकत और सोच सिर्फ भाजपा के पास है। दिल्ली का भविष्य चीजें मुफ्त बांटने से नहीं दूरगामी योजना बनाकर अमल करने से होगा। संकल्प पत्र में इसका ख्याल रखा गया है। उन्होंने कहा, भाजपा नेताओं को जब भी मौका मिला है, उन्होंने देश का भविष्य बदलने का काम किया है। मोदी सरकार ने दिल्ली में वायु प्रदूषण की समस्या हल करने के लिए 55 हजार करोड़ की लागत से सड़कें बनाई गई हैं। ईस्टर्न व वेस्टर्न पेरिफेरल पर 16 हजार करोड़ रुपये खर्च हुए हैं, इसे बनाने में दिल्ली सरकार ने पैसे नहीं दिए।

अप्रैल तक तैयार हो जाएगा दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेस वे पेज>>2